भारत - लीबिया संबंध

पृष्ठभूमि

हालांकि भूगोल के माध्यम से अलग - अलग होने के बावजूद भारत और लीबिया के बीच द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत है। भारत ने वर्ष 1969 में त्रिपोली में अपना राजनयिक मिशन स्थापित किया। भारत - लीबिया संबंधों की उच्च स्तरीय विशेषता वर्ष 1984 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की यात्रा थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लीबिया का समर्थन किया है। भारत ने 12 सितंबर, 2003 को अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1506 का स्वागत किया जिसके माध्यम से लीबिया पर से प्रतिबंध हटाए गए। हालांकि 17 फरवरी की क्रांति के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के मतदान ने छबि खराब करने और नकारात्मक सार्वजनिक धारणा के जन्म लेने का मार्ग प्रशस्त किया जिसे दुरूस्त करने में कुछ समय लग गया। जनरल नेशनल कांग्रेस (संसद) के पूर्व सभापति डॉ मोहम्मद यूसुफ मगरीफ ने 1970 के दशक के उत्तरार्ध में भारत में लीबिया के राजदूत के रूप में सेवा की थी और पूर्व प्रधानमंत्री डा. जिदान ने उनके अधीन कार्य किया था। लीबिया का नेतृत्व आज व्यावहारिक विदेश नीति पर चल रहा ह।

लीबिया की मुक्ति

20 अक्टूबर को गद्दाफी की हत्या के बाद लीबिया को औपचारिक रूप से 23 अक्तूबर को 'मुक्त' घोषित कर दिया गया। नवम्बर के उत्तरार्ध में अंतरिम सरकार का गठन किया गया।

भारत ने एन टी सी को मान्यता दी

भारत बिल्कुल शुरू से ही लीबिया की राष्ट्रीय संक्रमण परिषद (एन टी सी) के साथ लंदन, इस्तांबुल, पेरिस और न्यूयार्क में बात करती रही है तथा क्रांति के दौरान एन टी सी के प्रति अपने समर्थन से अवगत कराया। भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवीय सहायता आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से नकद रूप में 1 मिलियन अमरीकी डालर की मानवीय सहायता प्रदान की गई। भारत सरकार ने एन टी सी को अपनी औपचारिक मान्यता से 16 नवंबर 2011 को अवगत कराया। लीबिया के अनुरोध पर मानवीय सहायता की एक अन्य आपूर्ति भी जनवरी, 2012 त्रिपोली में एन टी सी को प्रदान की गई जिसके तहत मुख्य रूप से 1 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की जीवन रक्षक दवाएं तथा चिकित्सा उपकरण शामिल थे।

लीबिया इस समय एक नाजुक राजनीतिक एवं सुरक्षा स्थिति के दौर से गुजर रहा है। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए दूतावास द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए देश छोड़ने हेतु अनेक परामर्शी जारी की गई। अगस्त, 2014 से तकरीबन 3710 भारतीय नागरिकों को लीबिया से निकाला गया। मिशन को अस्थाई तौर पर डीजेर्बा (ट्यूनीशिया) ले जाया गया है तथा ट्रिपोली में नाममात्र का स्टाफ रोटेशन के आधार पर तैनात किया गया है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान द्विपक्षीय बातचीत

पिछले कुछ वर्षों में भारत एवं लीबिया के बीच उच्च स्तर पर अनेक यात्राएं हुई हैं। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री ईवीकेएस एलानगोवन ने भारत - लीबिया संयुक्त आयोग के 9वें सत्र में भाग लेने के लिए नवंबर, 2004 में लीबिया का दौरा किया। उसी माह, संसदीय कार्य एवं शहरी विकास मंत्री श्री गुलाम नवी आजाद ने भी लीबिया की ओर से निमंत्रण पर लीबिया का दौरा किया।

मई, 2005 में माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद ने लीबिया का दौरा किया। जुलाई, 2005 में माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने लीबिया का दौरा किया। जनवरी, 2007 में माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री मुरली देवड़ा ने लीबिया का दौरा किया। मई, 2007 में, माननीय विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने लीबिया का दौरा किया। सितंबर, 2009 में, राज्य सभा के उप सभापति श्री के रहमान खान ने लीबिया का दौरा किया। सितंबर, 2010 में, विदेश मंत्रालय में सचिव श्री जयंत प्रसाद ने लीबिया का अल्पावधिक दौरा किया। विदेश राज्य मंत्री श्री ई अहमद ने 14 से 16 अप्रैल, 2013 के दौरान लीबिया का दौरा किया तथा इस यात्रा के दौरान उन्होंने लीबिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से मुलाकात की तथा विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, तेल एवं गैस मंत्री तथा आवास एवं यूटिलिटी मंत्री के साथ चर्चा की। इसके अलावा, लीबिया के विदेश मंत्री माननीय श्री मोहम्मद अब्देलअजीज ने न्यूयार्क में सितंबर, 2013 में 68वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अतिरिक्ति समय में माननीय विदेश मंत्री से मुलाकात की। मुख्य रूप से क्षमता निर्माण के माध्यम से सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए त्रिपोली से एक उच्च स्तरीय सुरक्षा शिष्टमंडल ने 15 से 18 दिसंबर, 2013 के दौरान भारत का दौरा किया।

लीबिया की ओर से, मार्च, 2007 में एशियाई मामले मंत्री श्री बुरानी ने भारत का दौरा किया। जुलाई, 2007 में, आर्थिक, व्यापार एवं निवेश मंत्री श्री अल इसावी ने भारत - लीबिया संयुक्त आयोग के 10वें सत्र के अवसर पर भारत का दौरा किया। अप्रैल, 2008 में, अफ्रीकी मामले मंत्री डा. अब्दुस्सलाम ट्रेकी के नेतृत्व में लीबिया के एक शिष्टमंडल ने भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक में

भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। मार्च, 2009 में, कैप्टन रामादन, सचिव, बंदरगाह प्राधिकरण प्रशासन समिति (राज्य मंत्री) ने द्विपक्षीय पोत परिवहन करार पर वार्ता करने के लिए भारत का दौरा किया। वर्ष, 2010 में, संयुक्त्राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र के अध्यक्ष डा. ट्रेकी ने भारत का दौरा किया। जुलाई, 2011 में, लीबिया के विदेश मंत्री श्री अब्देलटी अल ओवैदी ने भारत का अल्पावधिक दौरा किया। सितंबर, 2012 में, विदेश मंत्रालय में महानिदेशक (एशिया) राजदूत रामदन रहीम के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया तथा लीबिया राजनयिक अकादमी एवं विदेश सेवा संस्थान के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय के डब्ल्यू ए एन ए प्रभाग एवं विदेश सेवा संस्थान के साथ परामर्श किया। नवंबर, 2012 में, लीबिया के उच्च राष्ट्रीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया तथा दोनों देशों के निर्वाचन आयोगों के बीच एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया गया। महानिदेशक (एशिया एवं आस्ट्रेलिया) के नेतृत्व में लीबिया के एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने फरवरी, 2014 के माह में दिल्ली में आयोजित महानिदेशक स्तरीय विदेश कार्यालय परामर्श में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया।

बंगलौर में फरवरी, 2013 में आयोजित एयर डिफेंस शो में भाग लेने के लिए लीबिया के एक रक्षा शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। भारत के संसद सदस्यों से बातचीत करने के लिए लीबिया के जनरल नेशनल कांग्रेस के एक 11 सदस्यीय संसदीय शिष्टमंडल ने अप्रैल, 2013 में भारत का एक अध्ययन दौरा किया। लीबिया के उप स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने नई दिल्ली में 26 से 28 अप्रैल, 2013 के दौरान स्वास्थ्य एवं स्वस्थता पर्यटन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिखर बैठक में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। अक्टूबर, 2013 में, त्रिपोली वाणिज्य चैंबर के अध्यक्ष तथा लीबिया व्यवसाय परिषद (एल बी सी) के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक 27 सदस्यीय मजबूत कारोबारी शिष्टमंडल ने 3 से 6 अक्टूबर, 2013 के दौरान मुंबई में भारत - अफ्रीका वाणिज्य चैंबर द्वारा आयोजित 'आई फॉर अफ्रीका' कार्यक्रम में भाग लिया। जनवरी, 2014 में, लीबिया के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक (एशिया) के नेतृत्व में लीबिया के एक शिष्टमंडल ने महानिदेशक स्तरीय विदेश कार्यालय परामर्श के लिए भारत का दौरा किया। मार्च, 2014 में, लीबिया के एक 10 सदस्यीय कारोबारी शिष्टमंडल ने बंगलौर में आयोजित मार्बल स्टोन एवं ग्रेनाइट (स्टोन) एक्सपो में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। संसद सदस्य श्री मोनेम अल यासर ने 19 से 22 मार्च, 2014 के दौरान विदेश मंत्रालय के सहयोग से ओ आर एफ द्वारा पश्चिम एशिया पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया तथा लीबियाई निजीकरण एवं निवेश बोर्ड (पी आई बी) के अध्यक्ष ने 9 से 11 मार्च, 2014 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित सी आई आई - एक्जिम बैंक गोष्ठी में भाग लिया। जून 2014 : अन्य बातों के साथ राजनयिक सुरक्षा एवं पुलिस प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने और पता लगाने के लिए आंतिरक मंत्रालय में प्रशिक्षण विभाग के सहायक निदेशक कर्नल रेडा अब्दुलहदी हल जलाह के नेतृत्व में एक पुलिस शिष्टमंडल ने 5 से 9 जून 2014 के दौरान भारत का दौरा किया।

द्विपक्षीय सहयोग :

भारत सरकार के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के तहत वर्ष 2014-15 के लिए लीबिया के लिए 20 स्लॉट आबंटित किए गए है। ये पूरी तरह वित्त पोषित अल्पावधिक तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं जिन्हें भारत की 50वीं प्रतिष्ठित संस्थाओं में 280 कार्यक्रमों के तहत प्रदान किया जाता है। आईटीईसी पाठ्यक्रमों के अलावा, विभिन्न अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी हैं जिसके लिए समय - समय पर नामांकन मंगाए जाते हैं।

अखिल अफ्रीकी ई-गवर्नेंस पहल शुरू होने के बाद टेली मेडिसीन, टेली एजुकेशन, ई गवर्नेंस आदि से संबंधित एक केंद्र लीबिया में स्थापित किया गया। इस पहल के तहत अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों को उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से भारत से जोड़ा जा रहा है। क्रांति के बाद इस केंद्र को फिर से चालू करने का कार्य प्रक्रिया के अधीन है तथा लीबिया में सुरक्षा की स्थिति में सुधार होने पर इसे शुरू किया जाएगा।

महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संधियां एवं करार

भारत एवं लीबिया के बीच निम्नलिखित करारों / समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:

- **दोहरे कराधान का परिहार तथा राजकोषीय उपवंचन की रोकथाम (1981);**
- **स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए करार (1983);**
- **आर्थिक सहयोग के लिए करार (1985);**
- **द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं संरक्षण करार (बी आई पी पी ए) (2007);**
- **सांस्कृतिक विनिमय करार (2007);**
- **दो निर्वाचन आयोगों के बीच 26 से 30 नवंबर 2012 में एम ओ यू;**

आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध

भारत और लीबिया के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंध हैं। वर्ष 1998 में, दोनों देशों ने "औद्योगिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक सहयोग पर प्रोटोकॉल" पर एक रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर किया। यह भारत - लीबिया संयुक्त आयोग (आई एल जे सी) के तहत दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए परामर्श की शुरूआत थी। अब तक आई एल जे सी के कुल 10 सत्रों का आयोजन हो चुका है।

दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के तहत वाणिज्यिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र शामिल हैं। 30 से अधिक साल से भारतीय कंपनियां लीबिया में सक्रिय हैं। प्रमुख भारतीय पीएसयू जैसे कि भेज, एन बी सी सी, ओ वी एल, आई ओ सी, ऑयल इंडिया तथा निजी कंपनियों जैसे कि पुंज लॉयड, यूनिटेक, के ई सी, एस एस बी, दस्तूर इंजीनियरिंग, शपूरजी पलोनजी, सेकॉन, ग्लोबल स्टील (इस्पात ग्रुप कंपनी), एन आई आई टी, सन फार्मा, सिम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स तथा डी एस कंस्ट्रक्शन द्वारा लीबिया में अनेक परियोजनाएं निष्पादित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत अस्पतालों, आवास, स्कूल, सड़क विद्युत संयंत्र, एयरपोर्ट, बांध, पारेषण लाइन आदि का निर्माण शामिल है।

विशेष रूप से तेल एवं गैस, विद्युत उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा निर्माण क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की लीबिया में अनेक परियोजनाएं हैं। इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया और ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड जैसी कंपनियां लीबिया में हाइड्रो कार्बन क्षेत्र में काम कर ही हैं। अप्रैल, 2014 में, पुंज लायड ज्लीटन शहर में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने करने के लिए 665 मिलियन अमरीकी डालर का ठेकदा प्राप्त किया। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) ने प्रतिष्ठित वेस्टर्न माउंटेन गैस टर्बाइन पावर प्रोजेक्ट का निष्पादन सफलता के साथ पूरा किया है। अनेक भारतीय आईटी कंपनियों जैसे कि जे एम आर, डी एस एस साफ्टवेयर, आई-फ्लेक्स सॉल्यूशन तथा अन्य कंपनियों के विशेष रूप से बैंकिंग के क्षेत्र में लीबिया की विभिन्न कंपनियों को साफ्टवेयर समाधान प्रदान करना जारी रखा है। अनेक भारतीय कंपनियां लीबिया में सुरक्षा की स्थिति सुधारने पर अपनी रूकी पड़ी परियोजनाओं को फिर से शुरू करना चाहती हैं।

भारत की ओर से आर्थिक - वाणिज्यिक यात्राएं :

भारत उद्योग परिसंघ (सी आई आई) के एक 14 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 30 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2012 के दौरान लीबिया का दौरा किया। इस शिष्टमंडल ने लीबिया व्यवसाय परिषद तथा वाणिज्य चैंबर के साथ अनेक अंत:क्रियात्मक बैठकें तथा सरकारी प्राधिकरणों जैसे कि आतंरिक मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि के साथ व्यक्तिगत बैठकें की। लीबिया के प्रधानमंत्री के साथ इस शिष्टमंडल की बैठक की भी व्यवस्था की गई जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल के तीन मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थिति थे।

ओवीएल के एक 2 सदस्यीय शिष्टमंडल ने 17-18 सितंबर, 2013 को त्रिपोली में आयोजित "तेल एवं गैस पर लीबिया फोरम" नामक सी डब्ल्यू सी में भाग लिया। मुख्य प्रबंध निदेशक श्री बी पी राव के नेतृत्व में भेल के एक 2 सदस्यीय तकनीकी शिष्टमंडल ने अपने विद्युत संयंत्र के पूरा होने के कार्य को अंतिम रूप देने के लिए लीबिया का दौरा किया तथा इसने ई सी सी की बोर्ड बैठक में भी भाग लिया। तीन भारतीय कंपनियों ने फार्मा एक्सपो में भाग लिया जिसका आयोजन 10 से 12

सितंबर, 2013 के दौरान किया गया। कुछ भारतीय कंपनियों ने 1 से 10 अक्टूबर, 2013 के दौरान 11वें त्रिपोली इंटरनेशनल बुक फेयर में भाग लिया जो 2011 की क्रांति के बाद पहली बार आयोजित हुआ था। जिसे वर्ष 2011 की क्रांति के बाद पहली बार आयोजित किया गया था। इसके अलावा, त्रिपोली वाणिज्य चेंबर के अध्यक्ष तथा लीबिया व्यवसाय परिषद (एल बी सी) के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक 27 सदस्यीय कारोबारी शिष्टमंडल ने 'आई फॉर अफ्रीका' कार्यक्रम में भाग लिया जिसे उसे 6 अक्टूबर, 2013 के दौरान मुंबई में भारत - अफ्रीका वाणिज्य चैंबर द्वारा आयोजित किया गया था। लीबिया के वित्त मंत्रालय के साथ आई ए एफ एस के तत्वावधान में कार्यपालक विकास कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आई आई एफ टी) की डा. तमन्ना चतुर्वेदी ने 24 -25 मार्च, 2014 को लीबिया का दौरा किया। अप्रैल, 2014 में, एक सफल 'भारतीय मंडप' का सफल आयोजन किया गया जिसमें उपभोक्ता उत्पाद क्षेत्र की लगभग 80 फर्मों ने भाग लिया। यह हाल के समय में सर्वोच्च भारतीय भागीदारी है तथा विदेशी राष्ट्रों की सबसे बड़ी भागीदारी है जिसमें 8 देशों ने भाग लिया। यह भागीदारी आई टी पी ओ के नेतृत्व में हुई जो फरवरी, 2011 की क्रांति के तीन साल बाद अफ्रीका के सबसे पुराने मेले में भारत की वापसी थी। इसके अलावा, व्यवसाय दर व्यवसाय बातचीत एवं बी एस एम के लिए 6 अप्रैल, 2014 को आई टी पी ओ द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित एक 'भारतीय दिवस' कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। एक 16 सदस्यीय सी ई ओ शिष्टमंडल ने भी 5 से 7 अप्रैल, 2014 के दौरान नए लीबिया में कारोबार के अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपोली का दौरा किया तथा अन्यों के अलावा जी एन सी के पहले उप राष्ट्रपति महामहिम श्री एजिदिन मोहम्मद अल-अवामी से भी मुलाकात की। वर्ष 2008-09 में लीबिया में शुरू की गई अखिल अफ्रीकी ई-नेटवर्क पहल को फिर से चालू करने में मदद से जुड़े प्रयासों के अंग के रूप में श्री जे के पांडेय, ग्रुप जनरल मैनेजर, टी सी आई एल (नोडल एजेंसी) ने 11 से 14 मई, 2014 के दौरान लीबिया का दौरा किया।

लीबिया की ओर से आर्थिक एवं वाणिज्यिक यात्राएं

17 से 19 मार्च, 2013 के दौरान भारत - अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर नई दिल्ली में आयोजित 9वीं सी आई आई - एक्जिम बैंक गोष्ठी में भाग लेने के लिए विदेश मंत्रालय के तकनीकी मामलों के सहायक अवर सचिव श्री सईद इब्राहिम अल खाट्टाली के नेतृत्व में लीबिया के एक 6 सदस्यीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। नई दिल्ली में 26 से 29 अप्रैल, 2013 के दौरान आयोजित "स्वास्थ्य एवं स्वस्थता पर्यटन बैठक" में भाग लेने के लिए लीबिया के स्वास्थ्य उप मंत्री अली साद सईद साद के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक 5 सदस्यीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। त्रिपोली वाणिज्य चैंबर के अध्यक्ष तथा लीबिया व्यवसाय परिषद (एल बी सी) के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक 27 सदस्यीय शिष्टमंडल ने मुंबई में 3 से 6 अक्टूबर, 2013 के दौरान भारत - अफ्रीका वाणिज्य चैंबर द्वारा आयोजित "आई फॉर अफ्रीका" कार्यक्रम में भाग लिया। कृषि उत्पादों का

व्यवासय करने वाले दो कारोबारियों ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 14 से 22 नवंबर, 2013 के दौश्रान आयोजित 33वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लिया। तेल एवं गैस मंत्री डा. अब्दुलबारी ए अरौसी के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय शिष्टमंडल ने द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी पेट्रोटेक में भाग लेने के लिए 12 से 14 नवंबर, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया। 12 से 15 फरवरी, 2015 के दौरान बंगलौर में आयोजित मार्बल स्टोन एवं ग्रेनाइट (स्टोना) एक्सपो में भाग लेने के लिए लीबिया के एक 10 सदस्यीय कारोबारी शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। लीबिया के निजीकरण एवं विदेश बोर्ड (पी आई बी) के अध्यक्ष ने 9 से 11 मार्च, 2014 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित सी आई आई - एक्जिम बैंक गोष्ठी में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। अप्रैल 2015 में जी एन सी त्रिपोली मुक्ति सरकार में विद्युत मंत्री श्री अहमद नूरेदिन अली सलेम ने भेल के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया। आई ए एफ एस के तहत वित्त मंत्रालय के साथ विदेश व्यापार एवं प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आई आई एफ टी के प्रतिनिधि डा. तमन्ना चतुर्वेदी ने 24 एवं 25 मार्च, 2014 को लीबिया का दौरा किया। वर्ष 2008-09 में लीबिया में शुरू की गई किंतु फरवरी 2011 की क्रांति के बाद अटकी हुई अखिल अफ्रीकी ई-नेटवर्क पहल को फिर से चालू करने में मदद से जुड़े प्रयासों के अंग के रूप में श्री जे के पांडेय, ग्रुप जनरल मैनेजर, टी सी आई एल (नोडल एजेंसी) ने 11 से 14 मई, 2014 के दौरान लीबिया का दौरा किया।

द्विपक्षीय व्यापार :

2014 - 2015 की अवधि के दौरान लीबिया को भारत द्वारा निर्यात 163.74 मिलियन अमरीकी डालर था और दूसरी और लीबिया से भारत द्वारा आयत 2014 - 2015 के दौरान 70.14 मिलियन अमरीकी डालर के आसपास था। मुख्य रूप से जुलाई 2014 से लीबिया में जारी राजनीतिक व गृह कलह एवं गृह युद्ध के कारण तेल के उत्पादन में कमी के कारण द्विपक्षीय व्यापार घट गया है। भारत की ओर से लीबिया को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें मुख्य रूप से पत्थर, प्लास्टर, तंबाकू, कॉफी, औषधि एवं भेषज पदार्थ तथा अन्य वस्तुएं शामिल हैं। लीबिया से भारत जिन वस्तुओं का आयात करता है उनमें मुख्य रूप से पेट्रोलियम (कच्चा एवं उत्पाद) तथा एल्युमीनियम अयस्क शामिल है।

भारत - लीबिया सांस्कृतिक संबंध

भारत और लीबिया ने विदेश मंत्री की लीबिया यात्रा के दौरान वर्ष 2007 में एक सांस्कृतिक विनिमय करार पर हस्ताक्षर किया है। पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) द्वारा प्रायोजित अनेक भारतीय सांस्कृतिक मंडलियों ने लीबिया का दौरा किया है तथा लीबिया

के प्रमुख शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए हैं। श्री कला मंडलम रमन कुट्टी के नेतृत्व में कथकली की एक 8 सदस्यीय मंडली ने अगस्त, 2008 में लीबिया का दौरा किया तथा त्रिपोली एवं सिर्ते में दो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रायोजित लीबिया की एक 8 सदस्यीय सांस्कृतिक मंडली ने पहली बार भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक के दौरान परफार्म करने के लिए भारत का दौरा किया, जो भारत में फरवरी 2008 में आयोजित हुई थी। एक 12 सदस्यीय 'अर्नात' कथक मंडली ने 16 से 22 नवंबर, 2009 के दौरान लीबिया का दौरा किया तथा तीन शहरों - त्रिपोली, सिर्ते और बैंघाजी में अपनी कला का प्रदर्शन किया। भारतीय गणतंत्र दिवस स्वागत समारोह के अवसर पर रेडिसन होटल, त्रिपोली में 26 जनवरी 2013 को महात्मा गांधी जी पर एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लीबिया के लोगों के अलावा उच्च पदाधिकारी, विदेशी राजनयिक एवं प्रख्यात भारतीय पहुंचे तथा उसे खूब सराहा गया।

नागरिक हड़ताल, सुरक्षा की कमजोर स्थिति के बावजूद मिशन ने त्रिपोली में 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

भारतीय समुदाय :

लीबिया में बगावत से पूर्व लीबिया में काम करने वाले भारतीयों की संख्या एक अनुमान के अनुसार 18000 के आसपास थी। भारतीय पेशेवर मुख्य रूप से अस्पतालों एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं में काम करते थे, जबकि जनशक्ति का अधिसंख्य हिस्सा निर्माण परियोजनाओं में काम करता था। क्रांति के दौरान फरवरी / मार्च, 2011 में भारत सरकार के खर्च पर उनमें से अधिकांश को वहां से निकालकर भारत लाया गया। क्रांति की अवधि के दौरान भी कुछ सौ भारतीय ने लीबिया में काम करना जारी रखा। क्रांति के दौरान लीबिया में भारतीय डाक्टरों एवं अर्ध चिकित्सा बलों द्वारा जो मदद एवं सहायता प्रदान की गई उसकी लीबिया के लोगों द्वारा सराहना की गई। धीरे - धीरे और भारतीय लीबिया लौट आए तथा वर्ष 2014 के पूर्वार्ध में उनकी संख्या 6000 के आसपास थी। माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने लीबिया से भारतीयों को पुन: निकालने का आदेश दिया और त्रिपोली, बेंघाजी तथा लीबिया के अन्य भागों में हिंसा एवं सशस्त्र संघर्ष में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2015 तक 3710 नागरिकों को लीबिया से निकाला गया। इसमें से 1324 लोगों को भारत सरकार की पूर्ण लागत से और 2386 लोगों को भारत सरकार की पूर्ण सुगमता से निकाला गया। लीबिया छोड़ने के लिए दूतावास की परामर्शी के बावजूद अभी भी तकरीबन 1850 भारतीय नागरिक लीबिया में हैं, जिन्होंने वापस जाने और अपना कार्य जारी रखने का निर्णय लिया है। स्थिति बिगड़ने की वजह से प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय (एम ओ आई ए) ने अगली सूचना तक ई सी आर श्रेणी के उत्प्रवास क्लीयरेंस की मंजूरी स्थगति कर दी है। भारतीय

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि लीबिया में रोजगार तक तब ग्रहण न करें जब तक कि सुरक्षा स्थिति स्थिर न हो जाए।

भारत के साथ हवाई संपर्क :

इस समय भारत से लीबिया के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है। जुलाई, 2014 में त्रिपोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नष्ट हो जाने के बाद त्रिपोली से वाणिज्यिक विदेशी एयरलाइंस की कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरती है। अब लीबिया की एयरलाइंस की सीमित उड़ानों के लिए मिटिगा एयरबेस का प्रयोग किया जा रहा है।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, लीबिया की वेबसाइट :
http://indianembassylibya.in/

****

जनवरी, 2016